



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 2 अप्रैल, 2010/12 चैत्र, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 अप्रैल, 2010

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5) 59/2009.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव बठूँह, तहसील ग्रामीण शिमला, जिला शिमला में तारादेवी गम्बर सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4 कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघा-विस्वा) में
शिमला	ग्रामीण शिमला	बढौह	104 / 1	0-1
			104 / 2	0-5
		कुल	किता-2	0-6

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव ।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2 31 मार्च, 2010

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5) 175/2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव चन्दुआ, तहसील देहरा, जिला कांगडा मे रानीताल कोटला सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र कांगडा) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है० में)
कांगडा	देहरा	चन्दुआ	476 / 1	0-01-29
			475 / 1	0-00-99
			1263 / 1	0-00-13
			1262 / 1	0-00-30
			1261 / 1	0-00-32
			1260 / 1	0-00-32
			1259 / 1	0-00-32
			1258 / 1	0-00-56
			1281 / 1	0-00-96
			680 / 1	0-00-35
			721 / 1	0-00-32
			722 / 1	0-00-28
			1339 / 728 / 1	0-00-16
			1340 / 728 / 1	0-00-51
			730 / 1	0-00-32
			731 / 1	0-01-85
			341 / 1	0-00-62
			1102 / 1	0-00-20
			1098 / 1	0-00-03
			907 / 1	0-01-38
			362	0-02-88
			909 / 1	0-00-18
			910 / 1	0-00-54
			911 / 1	0-00-42
			912 / 1	0-00-12
			914 / 1	0-02-16
			661 / 1	0-00-82
			366 / 1	0-00-20
			343 / 1	0-00-40
			346 / 1	0-00-45
			354 / 1	0-00-26
			913	0-08-97
			1103 / 1	0-00-22
			1104 / 1	0-00-20
			1105 / 1	0-02-11
			कुल किता 35	0-31-14

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / -
प्रधान सचिव।

लोक निर्माण विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 1 अप्रैल, 2010

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5) 154/2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव डकरैर, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा में भवारना-जससिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र कांगडा) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0 में)
कांगडा	पालमपुर	डकरैर	566 / 1	0-00-87
			कुल किता 1	0-00-87

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान।

लोक निर्माण विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 1 अप्रैल, 2010

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5) 174/2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव कलरु, तहसील देहरा, जिला कांगडा में भवारना-जससिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र कागड़ा) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0 में)
कांगडा	देहरा	कलरु	326 / 1	0-00-14
			कुल किता 1	0-00-14

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 अप्रैल, 2010

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5) 203/2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव कलर, उप तहसील हार चक्कियां, जिला कांगडा मे रानीताल कोटला सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा. 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र) कांगडा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	उप तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है० में)
कांगड़ा	हार चक्कियां	कलर	971 / 519 / 1	0-00-05
			973 / 519 / 1	0-00-28
			975 / 520 / 1	0-00-39
			521 / 1	0-00-16
			824	0-00-69
			825	0-00-39
			827	0-00-26
			761 / 1	0-00-39
			862 / 1	0-00-66
			863 / 1	0-00-06
			864 / 1	0-00-36
			865 / 1	0-00-18
			891 / 1	0-00-32
			892 / 1	0-00-40
			893 / 1	0-02-04
			916 / 1	0-00-07
			917 / 1	0-00-18
			918 / 1	0-03-51
			919 / 1	0-00-10
			920 / 1	0-00-63
			921 / 1	0-00-44
			922 / 1	0-00-48
			923 / 1	0-00-10
			940 / 1	0-01-74
			878	0-00-10
			कुल किता 25	0-13-98

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / -
प्रधान सचिव।

लोक निर्माण विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 1 अप्रैल, 2010

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5) 207 / 2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव पन्तेहड़, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा में भवारना-जससिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ० क्षेत्र कांगड़ा) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र(है० में)
कांगड़ा	कांगड़ा	पन्तेहड़	142 / 2	0-00-60
			151 / 1	0-01-71
			162 / 1	0-01-96
			311 / 1 / 2	0-01-00
			313 / 2 / 1	0-00-40
			700 / 1	0-00-30
			700 / 1 / 1	0-00-10
			759 / 1	0-00-27
			764 / 1	0-00-37
			765 / 1	0-00-18
			761 / 1	0-00-41
			1039 / 1	0-00-10
			1387 / 932 / 1	0-00-06
			1388 / 937 / 1	0-00-09
			कुल किता 14	0-07-55

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / —
प्रधान सचिव।

लोक निर्माण विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 1 अप्रैल, 2010

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5)202/2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव कमलयाला, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा में रानीताल कोटला सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ० क्षेत्र) कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है० में)
कांगड़ा	कांगड़ा	कमलयाला	22 / 1	0-00-62
			22 / 2	0-00-42
			96 / 1	0-00-99
			97 / 1	0-00-26
			98 / 1	0-00-68
			99 / 1	0-00-20
			298 / 1	0-00-37
			299 / 1	0-00-25
			300 / 1	0-00-42
			301 / 1	0-00-40
			324 / 1	0-00-14
			540	0-00-21
			559 / 1	0-00-24
			563 / 1	0-00-22
			564 / 1	0-00-35
			565 / 1	0-00-38
			565 / 1 / 1	0-00-60
			577 / 1	0-00-20
			579 / 1	0-00-05
			580 / 1	0-00-28
			581 / 1	0-01-02
			584 / 1	0-00-66

			585 / 1	0-00-20
			591 / 1	0-00-26
			592 / 1	0-00-06
			593 / 1	0-00-04
			594 / 1	0-00-10
			595 / 1	0-00-24
			598 / 1	0-00-10
			836 / 1	0-02-00
			843 / 1	0-00-62
			846 / 1	0-00-66
			847 / 1	0-00-66
			849 / 1	0-00-66
			921 / 1	0-00-75
			921 / 2	0-00-30
			कुल किता 36	0-15-61

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 अप्रैल, 2010

सं०पी०बी०डब्ल्यू०बी०एफ०(5)99 / 2009.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव महासू, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में चन्द्रनगर-हलाईला सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव 'एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (द० क्षेत्र) शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द० क्षेत्र) शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है०) में
शिमला	कोटखाई	महासू	113	0-07-50
			145	0-07-04
			480 / 1	0-04-12
			किता 3	0-18-66

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव।

लोक निर्माण विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 1 अप्रैल, 2010

सं0पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ0—(5) 9/2009.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव मूरिंग, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, में मूरिंग-डिलटा सड़क के निर्माण हेतु भूमि में अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	उप तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (विघा-विस्वा)
लाहौल एवं स्पिति	उदयपुर	मूरिंग	145 / 1	0-3-6
			145 / 2	0-1-10
			146 / 1	0-1-0
			147 / 1	0-6-3
			147 / 2	0-9-18
			150 / 1	1-0-0
		कुल जोड	किता-6	2-13-10

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग**अधिसूचना**

शिमला-171002, 29 मार्च, 2010

संख्या: सिंचाई: 11-30/2008-मण्डी.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव थुर्डा, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी में टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता,

भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र हैक्टेयर
मण्डी	सरकाघाट	थुर्ड़ / 355	738	0-01-44

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव।

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 26 मार्च, 2010

संख्या 7-243/2009-ई.एक्स.एन.-52602-623.—प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गये क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब ऐक्साईज ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन और इसके साथ पठित हिमाचल प्रदेश (ऐक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965, समय-समय पर यथा संशोधित द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जे० सी० शर्मा, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा हिमाचल प्रदेश स्वीट (मैन्युफैक्चर) रूलज, 1988 (जिन्हें इसके पश्चात् "उक्त रूलज" कहा गया है) में प्रथम अप्रैल, 2010 से निम्नलिखित और संशोधन करता हूं :-

In the existing rules.—

“In sub-clause (iii) of Rule 17-C of the said rules, after the letter, sign and word “L.5, the letter, sign and words “L.4A, L-5A” shall be inserted.”

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
आबकारी एवं कराधान आयुक्त।

EXCISE & TAXATION DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-171009, the 26th March, 2010*

No.7-243/2009-EXN-52602-623.—In exercise of the powers conferred by section 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) as in force in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organization Act, 1966 (31 of 1966) and by virtue of the powers of the Financial Commissioner, conferred on me under section 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Order, 1965, as amended from time to time, I, J.C. Sharma, Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh hereby make the following further amendment in the Himachal Pradesh Sweets (Manufacture) Rules, 1988 (hereinafter called the 'said rules') with effect from 1.4.2010 :—

In the existing rules.—

“In sub-clause (iii) of Rule 17-C of the said rules, after the letter, sign and word “L.5, the letter, sign and words “L.4A, L-5A” shall be inserted.”

By order,

Sd/-

Excise & Taxation Commissioner.

[Authoritative English Text of Excise & Taxation Department Notification No.7-243/2009-EXN-52602-623 Dated 26th March, 2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT*Shimla-171009, the 26th March, 2010*

No. 7-243/2009-EXN-52603-623.—In exercise of the powers conferred by section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner, conferred on me under section 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, J.C. Sharma, Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh hereby make the following further amendment in the Punjab Distillery Rules, 1932 as amended from time to time, applicable in the said areas (hereinafter called the “said rules”) with effect from 1.4.2010:—

AMENDMENT

In the said rules:—

1. In sub-rule (3) of Rule 9.5 for the words, signs and figures “Re.0.90” and “Re.0.70”, the words, signs and figures “Rs.1.00” and “Re.0.80” shall be substituted.
2. In second proviso to sub-rule (3) for the words, signs and figures, “Re.0.40” and “Re.0.20”, the words, signs and figures “Re.0.20” and “0.10” shall be substituted.

3. Sub-clause (d) of clause (e)(i) of Rule 9.93 shall be substituted by the following, namely :—

- (d) Bottling of IMFS shall be allowed in Glass bottles only w.e.f.1.4.2010. The country liquor is allowed to be bottled for the year 2010-11 in Pet bottles w.e.f.1.4.2010 to 31.5.2010 and 50% in Pet bottles & 50% in Glass bottles w.e.f. 1.6.2010 to 31.3.2011. Thereafter the country liquor shall be bottled in Glass bottles only in all sizes:

Provided that the manufacturers of the State are allowed to use assorted glass bottles with the word “H.P. Excise” sandblasted on these bottles.

By order,
Sd/-

Excise & Taxation Commissioner.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला—171009, 26 मार्च 2010

संख्या 7-243/2009-ई.एक्स.एन.-52603-623.—प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब ऐक्साईज ऐक्ट 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इसके साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन हिमाचल प्रदेश (ऐक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965, द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, जे० सी० शर्मा, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्वारा उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, पंजाब डिस्टिलरी रूलज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात “उक्त रूलज कहा गया है”) में प्रथम अप्रैल, 2010 से निम्नलिखित और संशोधन करता हूँ :—

संशोधन

In the existing rules;—

1. In sub-rule (3) of Rule 9.5 for the words, signs and figures “Re.0.90” and “Re.0.70”, the words, signs and figures “Rs.1.00” and “Re.0.80” shall be substituted.
2. In second proviso to sub-rule (3) for the words, signs and figures, “Re.0.40” and “Re.0.20”, the words, signs and figures “Re.0.20” and “0.10” shall be substituted.
3. Sub-clause (d) of clause (e)(i) of Rule 9.93 shall be substituted by the following, namely :—

- (d) Bottling of IMFS shall be allowed in Glass bottles only w.e.f.1.4.2010. The country liquor is allowed to be bottled for the year 2010-11 in Pet bottles w.e.f.1.4.2010 to 31.5.2010 and 50% in Pet bottles & 50% in Glass bottles w.e.f. 1.6.2010 to 31.3.2011. Thereafter the country liquor shall be bottled in Glass bottles only in all sizes:

Provided that the manufacturers of the State are allowed to use assorted glass bottles with the word "H.P. Excise" sandblasted on these bottles.

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
आबकारी एवं कराधान आयुक्त।

[Authoritative English Text of Excise & Taxation Department Notification No.7-243/2009-EXN-52603-23 Dated 26th March, 2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Shimla-171009, the 26th March, 2010

No. 7-243/2009-EXN-52603-623.—In exercise of the powers conferred by section 18 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) as applied to the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st in force in the territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966) and by virtue of the powers of the Financial Commissioner, conferred on me under section 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, as amended from time to time I, J.C. Sharma, Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh hereby make the following further amendment in the Punjab Distillery Rules, 1932 (hereinafter called the "said rules") as amended from time to time, and applicable in the said areas with effect from 1.4.2010:—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. In sub-rule (3) of Rule 5 for the words, signs and figures "Re.0.90" and "Re.0.70", the words, signs and figures "Rs.1.00" and "Re.0.80" shall be substituted.
2. In second proviso to sub-rule (3) for the words, signs and figures, "Re.0.40" and "Re.0.20", the words, signs and figures "Re.0.20" and "0.10" shall be substituted.
3. Sub-clause (d) of clause (e)(i) of Rule 93 shall be substituted by the following, namely:—

(d) Bottling of IMFS shall be allowed in Glass bottles only w.e.f.1.4.2010. The country liquor is allowed to be bottled for the year 2010-11 in Pet bottles w.e.f.1.4.2010 to 31.5.2010 and 50% in Pet bottles & 50% in Glass bottles w.e.f. 1.6.2010 to 31.3.2011. Thereafter the country liquor shall be bottled in Glass bottles only in all sizes:

Provided that the manufacturers of the State are allowed to use assorted glass bottles with the word "H.P. Excise" sandblasted on these bottles.

By order,
Sd/-
Excise & Taxation Commissioner.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 26 मार्च 2010

संख्या 7-243/2009-ई.एक्स.एन.-52603-623.—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को अन्तर्गत राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्साइज ऐक्ट 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन और इसके साथ पठित हिमाचल प्रदेश (एक्साइज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965, द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, जे० सी० शर्मा, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर यथा संशोधित, पंजाब डिस्टिलरी रूलज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात "उक्त रूलज कहा गया है") में प्रथम अप्रैल, 2010 से निम्नलिखित और संशोधन करता हूँ :—

संशोधन

In the said rules :—

1. In sub-rule (3) of Rule 5 for the words, signs and figures "Re.0.90" and "Re.0.70", the words, signs and figures "Rs.1.00" and "Re.0.80" shall be substituted.
2. In second proviso to sub-rule (3) for the words, signs and figures, "Re.0.40" and "Re.0.20", the words, signs and figures "Re.0.20" and "0.10" shall be substituted.
3. Sub-clause (d) of clause (e)(i) of Rule 93 shall be substituted by the following, namely:—
 - (d) Bottling of IMFS shall be allowed in Glass bottles only w.e.f.1.4.2010. The country liquor is allowed to be bottled for the year 2010-11 in Pet bottles w.e.f.1.4.2010 to 31.5.2010 and 50% in Pet bottles & 50% in Glass bottles w.e.f. 1.6.2010 to 31.3.2011. Thereafter the country liquor shall be bottled in Glass bottles only in all sizes:

Provided that the manufacturers of the State are allowed to use assorted glass bottles with the word "H.P. Excise" sandblasted on these bottles."

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
आबकारी एवं कराधान आयुक्त।

[Authoritative English Text of Excise & Taxation Department Notification No.7-243/2009-EXN-52603-623 Dated 26th March, 2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Shimla-171009, the 26th March, 2010

No. 7-243/2009-EXN-52603-623.—In exercise of the powers conferred by section 18 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the

Financial Commissioner, conferred on me under section 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, J.C. Sharma, Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Liquor Permit and Pass Rules, 1932 as amended from time to time (hereinafter called the "said rules") and as applicable in the said areas with effect from 1-4-2010:—

AMENDMENT

In the said rules:—

1. In Rule 7.22-A (1) for the words, signs and figures "Rs.2500/- (Rupee Two Thousand Five Hundred) appearing before the words "only for life time" the words, signs and figures "Rs.2,000/- (Rupee Two Thousand)" shall be substituted.
2. After Rule 7.23 new Rule 7.24 shall be added, namely :-

"The validity of the permits/ passes issued under these Permit and Pass Rules, is fixed as 'reasonable period' keeping in view the distance and topography between the place of dispatch and receipt of liquor."

By order,

Sd/-

Excise & Taxation Commissioner.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला—171009, 26 मार्च 2010

संख्या 7-243/2009-ई. एक्स.एन.-52603-623.—प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्साईज ऐक्ट 1914 (1914 का 1) की धारा 18 और 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इसके साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965, द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, जे० सी० शर्मा, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्वारा उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, पंजाब लिक्कर परमिट एण्ड पास रूलज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात "उक्त रूलज कहा गया है") में प्रथम अप्रैल, 2010 से निम्नलिखित और संशोधन करता हूँ :—

संशोधन

In the existing rules;—

1. In Rule 7.22-A (1) for the words, signs and figures "Rs.2500/- (Rupee Two Thousand Five Hundred)" appearing before the words "only for life time" the words, signs and figures "Rs.2,000/- (Rupee Two Thousand)" shall be substituted.

2. After Rule 7.23 new Rule 7.24 shall be added, namely :—

“The validity of the permits/ passes issued under these Permit and Pass Rules, is fixed as ‘reasonable period’ keeping in view the distance and topography between the place of dispatch and receipt of liquor.”

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
आबकारी एवं कराधान आयुक्त।

[Authoritative English Text of Excise & Taxation Department Notification No.7-243/2009-EXN-52603-623 Dated 26th March, 2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Shimla-171009, the 26th March, 2010

No. 7-243/2009-EXN-52603-623.—In exercise of the powers conferred by section 18 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) as in force in the territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organization Act, 1966 (31 of 1966) and by virtue of the powers of the Financial Commissioner, conferred on me under section 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, as amended from time to time I, J.C. Sharma, Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh hereby make the following further amendment in the Punjab Liquor Permit and Pass Rules, 1932 (hereinafter called the “said rules”) as amended from time to time, and applicable in the said areas with effect from 1.4.2010:—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. In Rule 22-A (1) for the words, signs and figures “Rs.2500/- (Two Thousand Five Hundred)” appearing before the words “only for life time” the words, signs and figures “Rs.2,000/- (Rupee Two Thousand)” shall be substituted.
2. After Rule 23 new Rule 24 shall be added, namely :-

“The validity of the permits/ passes issued under these Permit and Pass Rules, is fixed as ‘reasonable period’ keeping in view the distance and topography between the place of dispatch and receipt of liquor.”

By order,
Sd/-
Excise & Taxation Commissioner.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 26 मार्च 2010

संख्या 7-243/2009-ई.एक्स.एन.-52603-623.—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को अन्तर्गत राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्साईज ऐक्ट 1914 (1914 का 1) की धारा 18 और 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन और इसके साथ पठित हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965, द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, जे० सी० शर्मा, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर यथा संशोधित, पंजाब लिक्कर परमिट एण्ड पास रूलज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात "उक्त रूलज कहा गया है") में प्रथम अप्रैल, 2010 से निम्नलिखित और संशोधन करता हूँ :-

संशोधन

In the said rules :—

1. In Rule 22-A (1) for the words, signs and figures "Rs.2500/- (Two Thousand Five Hundred)" appearing before the words "only for life time" the words, signs and figures "Rs.2,000/- (Rupee Two Thousand)" shall be substituted.

2. After Rule 23 new Rule 24 shall be added, namely :-

"The validity of the permits/ passes issued under these Permit and Pass Rules, is fixed as 'reasonable period' keeping in view the distance and topography between the place of dispatch and receipt of liquor."

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
आबकारी एवं कराधान आयुक्त।

[Authoritative English Text of Excise & Taxation Department Notification No. 7-243/2009-EXN-52603-623 Dated 26th March, 2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-171009, the 26th March, 2010*

No.7-243/2009-EXN-52603-623.—In exercise of the powers conferred by section 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914), as in force in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the Territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-Organisation Act, 1966 (31 of 1966) and by virtue of the powers of the Financial Commissioner, conferred on me under section 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Power and Appeal) Orders, 1965, I, J.C. Sharma, Excise and Taxation

Commissioner, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 1.4.2010 :—

AMENDMENT

In the said rules:—

1. In rule 1-

- (i) For the words “Not renewable” appears against entry L-2-A (Ahata) in column 5 shall be substituted by the words “Collector”.
- (ii) Against the entry L.5-A after the word “beer”, the words “cider and wine” shall be inserted.
- (iii) For the words “Not renewable” appears against entry L-14-C (Ahata) in column 5 shall be substituted by the words “Collector”.

2. After clause (i) of Rule 22, the following proviso shall be added, namely :-
“Provided that the L-13 vend may be changed from one place to the other if the maximum of the retail vendors to whom liquor is supplied by such wholesale vend is situated at a different ETI/ETO Circle, keeping in view the recommendations of the AETC I/C of the District and on application to the Collector (Excise) of the concerned zone after the approval of the Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh if the trend of consumption for at least two quarters of the current year indicates so.”

3. In Rule 23-A, after the words ‘granted’ appearing in first line, the sign and word “/renewed” shall be added.

4. In Rule-35-

After sub-rule (25) of Rule 35-A, the following proviso shall be added, namely:-
“Provided that after lifting of 80% quota of annual quota upto 31st December, 15% additional quota may granted by the Collector’s (Excise) of the concerned Zones provided that the balance regular quota is lifted and license fee is recovered before the issuance of passes of the additional quota.”

5. Sub-clause (d) of sub-rule (31) of Rule 37 shall be substituted by the following, namely :-

- (d) Bottling of IMFS shall be allowed in Glass bottles only w.e.f.1.4.2010. The country liquor is allowed to be bottled for the year 2010-11 in Pet bottles w.e.f.1.4.2010 to 30.5.2010 and in the ratio of 50% in Pet bottles & 50% in Glass bottles w.e.f. 1.6.2010 to 31.3.2011. Thereafter the country liquor shall be bottled in Glass bottles only in all sizes.

6. In Rule-38-

- (a) After clause (f) of sub-rule (1) of Rule 38, the following proviso shall be added, namely:-

“Provided that the L-1 vend may be changed from one place to the other if the maximum of the retail vendors to whom liquor is supplied by such wholesale vend is situated at a different ETI/ETO Circle, keeping in view the

recommendations of the AETC I/C of the District and on application to the Collector (Excise) of the concerned zone after the approval of the Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh if the trend of consumption for at least two quarters of the current year indicates so.

- (b) After clause (c) of sub-rule (2) of Rule-38, the following clause (d) shall be inserted, namely:-

“(d) The retail L-2 licensee is required to stamp and sign each bottle of IMFL issued to the bar licenses against the excise passes.”

- (c) Clause (iii) of sub-rule (1-BB) of Rule 38 shall be substituted by the following, namely :-

“(iii) the licensee shall not sell brands of imported foreign liquor unless such brands have been registered with the Financial Commissioner on payment of Rs.1000/- per brand in case of all liquor excluding wine and cider and in the case of wine or cider on payment of Rs.1.00 per brand.”

- (d) In sub-rule (2-A) of Rule 38.—

(i) After the word, ‘granted’ appearing in first line, the sign and word “/renewed” shall be added.

(ii) In clause (a) after the word ‘granted, the sign and word “/renewed” shall be added.

(iii) In clause (c) after the word ‘granted, the sign and word “/renewed” shall be added.

- (e) After clause (n) of sub-rule (21) of Rule 38, the following clause (o) shall be added, namely:-

“(o) The retail L-14/L-14-A licensee in rural areas is required to stamp and sign each bottle of IMFL issued to the bar licenses against the excise passes.”

7. In Schedule-A appended to this Rule.—

- (i) The annual fixed license fee in respect of L-1 license appearing at Sr.No.1 in column No. 3 shall be substituted by Rs.3,00,000/- instead of Rs.2,00,000/-.
- (ii) The annual minimum fixed license fee in respect of L-1-B license appearing at Sr.No.3 (i) in column No.3 shall be substituted by Rs.75000/- instead of Rs. 50,000/-.
- (iii) The annual minimum fixed license fee in respect of L-1-BB license appearing at Sr.No.4 in column No.3 shall be substituted by Rs.40,000/- instead of Rs.25,000/-.
- (iv) The annual fixed license fee in respect of L-13 license appearing at Sr.No.20 (i) in column No.3 shall be substituted by Rs.80,000/- instead of Rs.50,000/-.

8. The Schedule-B appended to this Rule shall be substituted by the following, namely :-

SCHEDULE 'B'**(i) Rates of Assessed fee for licenses inform L.3, L.4, L.5, L.3A, L.4A, L.5A, L.12A, L.12B and L.12C**

Sr. No	Kind of liquor	Rate of assessed fee per bulk litre.
1.	Foreign Spirit- (i) Indian Made Foreign Spirit (ii) Imported Spirit (B.I.I)* (iii) Imported Spirit (B.I.O).**	Rs.152.00 Rs.187.00 Rs.210.00
2.	Wine and Cider- (i) Imported (B.I.O) Indian Made (imported through the source of S-1B only and subsequently sold through L.1)	Rs. 30.00 Rs. 20.00
3.	Beer- (i) Imported (B.I.O) (ii) Indian Made (iii) Draught beer	Rs. 32.00 Rs. 22.00 Rs. 30.00
4.	Ready To Drink Beverages	Rs. 20.00

(ii) Rates of Assessed fee for licenses in form L-9.

Sr. No.	Kind of liquor	Rate of assessed fee per bulk litre
1.	(i) Indian Made Foreign Spirit- (a) Rum (b) Cheap and Regular (c) Premium (d) Deluxe including Imported Spirit (B.I.I.). (ii) Imported Spirit (B.I.O)	Rs. 70.00 Rs. 75.00 Rs. 94.00 Rs.140.00 Rs.145.00
2.	Wine	Rs. 5.00
3.	Cider	Rs. 1.00
4.	Beer (i) Imported (B.I.O) (ii) Indian Made	Rs.13.00 per bottle of 650 mls Rs. 10.00 per bottle of 650 mls.

(iii) Rates of Assessed fee for licenses in form L.10.BB.

(a) Beer for L.10BB- (i) Imported (B.I.O.) (ii) Indian Made	Rate of assessed fee per bulk litre.
	Rs. 29.00 Rs. 20.00
(b) Wine and Cider- (i) Imported (B.I.O) (ii) Indian Made (imported through the source of S-1B only and subsequently sold through L.1) (c) Ready To Drink Beverages	Rs. 27.00 Rs. 18.00 Rs. 18.00

* B.I.I. - Bottled in India

** B.I.O. - Bottled in Original.

These rates shall also be leviable on the Indian Made Cider sold at the S.1A vends.

9. The Schedule-C appended to this Rule shall be substituted by the following, namely :-

SCHEDULE 'C'

The rates of Application fee for allotment, Renewal fee, Basic license fee and Annual license fee :-

(1) **Application** fee for allotment = Rs.15,000/-

(2) (a) Renewal fee per vend :--

Sr. No.	Value of vend	Renewal Fee
(i)	Upto Rs.15 lac	Rs. 17,500/-
(ii)	Above Rs.15 lac upto Rs.25 lac	Rs. 34,500/-
(iii)	Above Rs.25 lac upto Rs.50 lac	Rs. 52,000/-
(iv)	Above Rs.50 lac	Rs. 70,000/-

(b) Renewal fee of Country Fermented Liquor vend

Sr. No.	Value of vend	Renewal Fee
(i)	Upto Rupees One lac	Rs. 5,000/-
(ii)	Above Rs.1.00 lac upto Rs.10 lac	Rs. 10,000/-
(iii)	Above Rs.10 lac	Rs. 15,000/-

(3) **Basic License fee**—

Sr. No.	Minimum Guaranteed Quota of the Unit	Basic license fee
1.	Upto 15000 Pls	Rs. 25,000.00
2.	Above 15000 to 25000 Pls	Rs. 35,000.00
3.	Above 25000 to 35000 Pls	Rs. 45,000.00
4.	Above 35000 to 45000 Pls	Rs. 55,000.00
5.	Above 45000 to 65000 Pls	Rs. 70,000.00
6.	Above 65000 to 80000 Pls	Rs. 80,000.00
7.	Above 80000 to 100000 Pls	Rs. 1,00,000.00
8.	Above 100000 to 200000 Pls	Rs. 2,00,000.00
9.	Above 200000 Pls	Rs. 5,00,000.00

(4) **License fee-**

Kind of liquor Rate of license fee.

Country Liquor	Rs.113/- per proof litre.
Foreign Spirit-	
Indian Made Foreign Spirit	Rs.157/- per proof litre.
Foreign Spirit (B.I.I)	Rs. 170/- per proof litre.
Foreign Spirit (B.I.O.)	Rs.200/- per proof litre
Beer	
Indian Made	Rs.20/- per bulk litre
Imported Beer (B.I.O)	Rs.29/- per bulk litre.
Wine & Cider	
(i) Indian Made (imported through some of S-B and subsequently sold through L.1)	Rs.18/- per bulk litre
(ii) Imported (B.I.O)	Rs.27/- per bulk litre.
Ready To Drink Beverages	Rs.18/- per bulk litre.

By order,
Sd/-

Excise & Taxation Commissioner.

आबकारी एवं कराधान विभाग**अधिसूचना**

शिमला-171009, 26 मार्च, 2010

संख्या 7-243 / 2009-ई.एक्स.एन.-52603-623.—प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गये क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब ऐक्साईज ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन और इसके साथ पठित हिमाचल प्रदेश (ऐक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डर, 1965 द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, जे० सी० शर्मा, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्वारा हिमाचल प्रदेश लिकर लाईसेंस रूलज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात "उक्त रूलज" कहा गया है) में 1-4-2010 से और संशोधन करता हूँ:-

संशोधन**1. In rule 1-**

- (i) For the words "Not renewable" appears against entry L-2-A (Ahata) in column 5 shall be substituted by the words "Collector".
- (ii) Against the entry L-5-A after the word "beer", the words "cider and wine" shall be inserted.
- (iii) For the words "Not renewable" appears against entry L-14-C (Ahata) in column 5 shall be substituted by the words "Collector".

2. After clause (i) of Rule 22, the following proviso shall be added, namely :-
"Provided that the L-13 vend may be changed from one place to the other if the maximum of the retail vendors to whom liquor is supplied by such wholesale vend is situated at a different ETI/ETO Circle, keeping in view the recommendations of the AETC I/C of the District and on application to the Collector (Excise) of the concerned zone after the approval of the Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh if the trend of consumption for at least two quarters of the current year indicates so.

3. In Rule 23-A after the words 'granted' appearing in first line, the sign and word "/renewed" shall be added.

4. In Rule-35-

- (i) After sub-rule (25) of Rule 35-A, the following proviso shall be added, namely:-
"Provided that after lifting of 80% quota of annual quota upto 31st December, 15% additional quota may granted by the Collector's (Excise) of the concerned Zones provided that the balance regular quota is lifted and license fee is recovered before the issuance of passes of the additional quota.

5. Sub-clause (d) of sub-rule (31) of Rule 37 shall be substituted by the following, namely :-

- (d) Bottling of IMFS shall be allowed in Glass bottles only w.e.f.1.4.2010. The country liquor is allowed to be bottled for the year 2010-11 in Pet bottles

w.e.f. 1.4.2010 to 30.5.2010 and ratio of 50% in Pet bottles & 50% in Glass bottles w.e.f. 1.6.2010 to 31.3.2011. Thereafter the country liquor shall be bottled in Glass bottles only in all sizes.

6. In Rule-38-

- (a) After clause (f) of sub-rule (1) of Rule 38, the following proviso shall be added, namely:-

“Provided that the L-1 vend may be changed from one place to the other if the maximum of the retail vendors to whom liquor is supplied by such wholesale vend is situated at a different ETI/ETO Circle, keeping in view the recommendations of the AETC I/C of the District and on application to the Collector (Excise) of the concerned zone after the approval of the Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh if the trend of consumption for at least two quarters of the current year indicates so.

- (b) After clause (c) of sub-rule (2) of Rule-38, the following clause (d) shall be inserted, namely:-

“(d) The retail L-2 licensee is required to stamp and sign each bottle of IMFL issued to the bar licenses against the excise passes.”

- (c) Clause (iii) of sub-rule (1-BB) of Rule 38 shall be substituted by the following, namely :-

“(iii) the licensee shall not sell brands of imported foreign liquor unless such brands have been registered with the Financial Commissioner on payment of Rs.1000/- per brand in case of all liquor excluding wine and cider and in the case of wine or cider on payment of Rs.1.00 per brand.”

- (d) In sub-rule (2-A) of Rule 38.—

- (i) After the word, ‘granted’ appearing in first line, the sign and word “/renewed” shall be added.
 (ii) In clause (a) after the word ‘granted, the sign and word “/renewed” shall be added.
 (iii) In clause (c) after the word ‘granted, the sign and word “/renewed” shall be added.

- (e) After clause (n) of sub-rule (21) of Rule 38, the following clause (o) shall be added, namely:-

“(o) The retail L-14/L-14-A licensee in rural areas is required to stamp and sign each bottle of IMFL issued to the bar licenses against the excise passes.”

7. In Schedule-A appended to this Rule.--

- (i) The annual fixed license fee in respect of L-1 license appearing at Sr.No.1 in column No.3 shall be substituted by Rs.3,00,000/- instead of Rs.2,00,000/-.
 (ii) The annual minimum fixed license fee in respect of L-1-B license appearing at Sr.No.3 (i) in column No.3 shall be substituted by Rs.75000/- instead of Rs.50,000/-.
 (iii) The annual minimum fixed license fee in respect of L-1-BB license appearing at Sr.No.4 in column No.3 shall be substituted by Rs.40,000/- instead of Rs.25,000/-.
 (iv) The annual fixed license fee in respect of L-13 license appearing at Sr.No.20 (i) in column No.3 shall be substituted by Rs.80,000/- instead of Rs.50,000/-.

8. The Schedule-B appended to this Rule shall be substituted by the following, namely :-

SCHEDULE 'B'

(i) **Rates of Assessed fee for licenses inform L.3, L.4, L.5, L.3A, L.4A, L.5A, L.12A, L.12B and L.12C**

(i) **Rates of Assessed fee for licenses inform L.3, L.4, L.5, L.3A, L.4A, L.5A, L.12A, L.12B and L.12C**

Sr. No	Kind of liquor	Rate of assessed fee per bulk litre.
1.	Foreign Spirit- (i) Indian Made Foreign Spirit (ii) Imported Spirit (B.I.I)* (iii) Imported Spirit (B.I.O).**	Rs.152.00 Rs.187.00 Rs.210.00
2.	Wine and Cider- (i) Imported (B.I.O) Indian Made (imported through the source of S-1B only and subsequently sold through L.1)	Rs. 30.00 Rs. 20.00
3.	Beer- (i) Imported (B.I.O) (ii) Indian Made (iii) Draught beer	Rs. 32.00 Rs. 22.00 Rs. 30.00
4.	Ready To Drink Beverages	Rs. 20.00

(ii) **Rates of Assessed fee for licenses in form L-9.**

Sr. No.	Kind of liquor	Rate of assessed fee per bulk litre
1.	(i) Indian Made Foreign Spirit- (a) Rum (b) Cheap and Regular (c) Premium (d) Deluxe including Imported Spirit (B.I.I.). (ii) Imported Spirit (B.I.O)	Rs. 70.00 Rs. 75.00 Rs. 94.00 Rs.140.00 Rs.145.00
2.	Wine	Rs. 5.00
3.	Cider	Rs. 1.00
4.	Beer (i) Imported (B.I.O) (ii) Indian Made	Rs.13.00 per bottle of 650 mls Rs. 10.00 per bottle of 650 mls.

(iii) **Rates of Assessed fee for licenses in form L.10.BB.**

(a) Beer for L.10BB- (i) Imported (B.I.O.) (ii) Indian Made	Rate of assessed fee per bulk litre. Rs. 29.00 Rs. 20.00
(b) Wine and Cider- (i) Imported (B.I.O) (ii) Indian Made (imported through the source of	Rs. 27.00 Rs. 18.00

S-1B only and subsequently sold through L.1)	
(c) Ready To Drink Beverages	Rs. 18.00

* B.I.I. - Bottled in India

** B.I.O. - Bottled in Original.

These rates shall also be leviable on the Indian Made Cider sold at the S.1A vends.

9. The Schedule-C appended to this Rule shall be substituted by the following, namely :-

SCHEDULE 'C'

The rates of Application fee for allotment, Renewal fee, Basic license fee and Annual license fee : -

(1) **Application** fee for allotment = Rs.15,000/-

(2) (a) Renewal fee per vend :--

Sr. No.	Value of vend	Renewal Fee
(i)	Upto Rs.15 lac	Rs. 17,500/-
(ii)	Above Rs.15 lac upto Rs.25 lac	Rs. 34,500/-
(iii)	Above Rs.25 lac upto Rs.50 lac	Rs. 52,000/-
(iv)	Above Rs.50 lac	Rs. 70,000/-

(b) Renewal fee of Country Fermented Liquor vends

Sr. No.	Value of vend	Renewal Fee
(i)	Upto Rupees One lac	Rs. 5,000/-
(ii)	Above Rs.1.00 lac upto Rs.10 lac	Rs. 10,000/-
(iii)	Above Rs.10 lac	Rs. 15,000/-

(3) **Basic License fee—**

Sr. No.	Minimum Guaranteed Quota of the Unit	Basic license fee
1.	Upto 15000 Pls	Rs. 25,000.00
2.	Above 15000 to 25000 Pls	Rs. 35,000.00
3.	Above 25000 to 35000 Pls	Rs. 45,000.00
4.	Above 35000 to 45000 Pls	Rs. 55,000.00
5.	Above 45000 to 65000 Pls	Rs. 70,000.00
6.	Above 65000 to 80000 Pls	Rs. 80,000.00
7.	Above 80000 to 100000 Pls	Rs. 1,00,000.00
8.	Above 100000 to 200000 Pls	Rs. 2,00,000.00
9.	Above 200000 Pls	Rs. 5,00,000.00

(4) License fee-

Kind of liquor Rate of license fee.

Country Liquor	Rs.113/- per proof litre.
Foreign Spirit-	
Indian Made Foreign Spirit	Rs.157/- per proof litre.
Foreign Spirit (B.I.I)	Rs. 170/- per proof litre.
Foreign Spirit (B.I.O.)	Rs.200/- per proof litre
Beer	
Indian Made	Rs.20/- per bulk litre
Imported Beer (B.I.O)	Rs.29/- per bulk litre.
Wine & Cider	
(i) Indian Made (imported through some of S-B and subsequently sold through L.1)	Rs.18/- per bulk litre
(ii) Imported (B.I.O)	Rs.27/- per bulk litre.
Ready To Drink Beverages	Rs.18/- per bulk litre.

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
आबकारी एवं कराधान आयुक्त।

न्यायालय श्री देवा सिंह नेगी (हि0प्र0से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी भरमौर, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी चलेड, डाकघर ग्रीमा, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा (13) 3 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी चलेड, डाकघर ग्रीमा, तहसील भरमौर, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र इस न्यायालय में दिया है कि उसका लड़का विजय कुमार जिसकी जन्म तिथि 6-7-07 है पंचायत अभिलेख ग्रीमा में दर्ज नहीं है अब दर्ज करने बारे न्यायालय से अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया है कि यदि उपरोक्त विजय कुमार का नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख ग्रीमा में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर एतराज असातन या बकालतन इशतहार जारी होने के एक मास के भीतर इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

इशतहार आज दिनांक 12-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देवा सिंह नेगी,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी भरमौर,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

न्यायालय श्री देवा सिंह नेगी (हि0प्र0से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी भरमौर, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री दौलत राम पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी चलेड, डाकघर ग्रीमा, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा (13) 3 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दौलत राम पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी चलेड, डाकघर ग्रीमा, तहसील भरमौर, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र इस न्यायालय में दिया है कि उसका लड़का उमेश कुमार जिसकी जन्म तिथि 8-8-2006 है पंचायत अभिलेख ग्रीमा में दर्ज नहीं है अब दर्ज करने बारे न्यायालय से अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया है कि यदि उपरोक्त उमेश कुमार का नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख ग्रीमा में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर/एतराज असालतन या वकालतन इशतहार जारी होने के एक मास के भीतर इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

इशतहार आज दिनांक 12-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देवा सिंह नेगी,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी भरमौर,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

न्यायालय श्री देवा सिंह नेगी (हि0प्र0से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी भरमौर, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री रतन चन्द पुत्र श्री जयकरण, निवासी गुवाड, डाकघर भराडी, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा (13) 3 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रतन चन्द पुत्र श्री जयकरण, निवासी गुवाड, डाकघर भराडी, तहसील भरमौर, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र इस न्यायालय में दिया है कि उसका लड़का राजेश कुमार जिसकी जन्म तिथि 20-3-2003 है पंचायत अभिलेख सांह में दर्ज नहीं है अब दर्ज करने बारे न्यायालय से अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया है कि यदि उपरोक्त राजेश कुमार का नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख सांह में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर/एतराज असालतन या वकालतन इशतहार जारी होने के एक मास के भीतर इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

इशतहार आज दिनांक 12-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।

देवा सिंह नेगी,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी भरमौर,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री चन्दन कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा :

श्री जिया लाल पुत्र श्री गंगा राम, निवासी जलारुण, डाकघर प्रेशी, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री जिया लाल पुत्र श्री गंगा राम, गांव जलारुण, डाकघर प्रेशी, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थन-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी की पुत्री का नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया गया जिसको प्रार्थी पंचायत अभिलेख में कुमारी अंजना की जन्म तिथि 19-12-2002 है को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर एतराज हो तो दिनांक 3-4-2010 को सुबह 10.00 बजे इस कार्यालय में असालतन व वकालतन पेश करें अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15-3-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

चन्दन कपूर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री चन्दन कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा :

श्री जय राम पुत्र श्री परस राम, निवासी बाढ़ू, डाकघर दोघरी, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री जय राम पुत्र श्री परस राम, गांव बाढ़ू, डाकघर दोघरी, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थन-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी की दो पुत्रियों की जन्म तिथियां ग्राम पंचायत अभिलेख में कुमारी सुनीता की जन्म तिथि 10-7-1995 लिखी है जबकि इसकी वास्तविक जन्म तिथि

10-7-1991 है तथा कुमारी भारा देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में 15-11-1996 है जो गलत है। वास्तविक जन्म तिथि 15-11-1992 सही है।

अतः इस इशतहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर एतराज हो तो दिनांक 3-4-2010 को सुबह 10.00 बजे इस कार्यालय में असालतन व वकालतन पेश करें अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 3-3-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

चन्दन कपूर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री चन्दन कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा :

श्री फिहनू राम पुत्र श्री मान दास, निवासी जरल, डाकघर बटवाड़ा, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री फिहनू-सोहन सिंह पुत्र श्री मान दास, गांव जरल, डाकघर बटवाड़ा, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थन-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी का नाम पंचायत अभिलेख व राजस्व अभिलेख में अलग नामों से लिखा गया है। जिससे प्रार्थी को असुविधा हो रही है जिसको पंचायत अभिलेख व राजस्व अभिलेख में सोहन सिंह उर्फ फिहनू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को इस बारा कोई भी उजर एतराज हो तो दिनांक 3-4-2010 को सुबह 10.00 बजे इस कार्यालय में असालतन व वकालतन पेश करें अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 3-3-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

चन्दन कपूर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 16th March, 2010

Subject.—Appointment of Public Information Officers and Assistant Public Information Officers for Medical College, Shimla and Dr. RPGMC, Kangra at Tanda at under the RTI Act, 2005.

No HFW-B(A)1-5/2005.—I am directed to refer to your letter No. HFW-H(DRRPGMC)/P/F-26517 and 19127-28 dated 18-11-2009 and in suppression of this department Letter No. HFW-B(A)2-1/2007 dated 28-3-2007, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to declare the following Officers “as Appellate Authority, Public Information Officers and Assistant Information Officers who shall be responsible for discharging the functions of appellate Authority, State Public Information and Assistant Public Information Officer under the various provisions of the Right to Information Act with immediate effect, in the public interest :—

1. Director of Medical Education and Research, Shimla :

- | | | |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Appellate Authority | Director, Medical Education and Research, (H. P.) |
| 2. | Public Information Officer | Section Officer (F&A) in place of Addl. Director as existing officer is not in the establishment of Director, Medical Education and Research (H. P.). |

2. Indira Gandhi Medical College, Shimla :

- | | | |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. | Appellate Authority | Principal, IGM, Shimla |
| 2. | Public Information Officer for IGM, Shimla. | Administrative officer, IGM, Shimla |
| 3. | Public Information Officer for IG and KNH, hospital, Shimla. | Sr. Medical Superintendent, IGM, Shimla |
| 4. | Public Information Officer for Rogi Kalyan Samiti, Shimla. | Deputy Controller (F&A), IGM, Shimla |

3. Dr. RPGMC, Kangra at Tanda :

- | | | |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Appellate Authority | Principal, Dr. RPGMC, Kangra at Tanda |
| 2. | Public Information Officer for college. | Law Officer, Tanda |
| 3. | Public Information Officer for hospital. | Sr. Medical Supdt. Tanda |
| 4. | Public Information Officer for Rogi Kalyan Samiti. | -do- |

4. H. P. Dental College, Shimla :

- | | | |
|----|----------------------------|----------------------------------|
| 1. | Appellate Authority | Principal Dental College |
| 2. | Public Information Officer | Administrative Controller)F&A). |

By order,
Sd/-
Addl. Secretary .

सामान्य प्रशासन विभाग

ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 01 अप्रैल, 2010

संख्या: जीएडी-बी(बी)15-1/2010.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, जनगणना नियम, 1990 के नियम 6 के साथ पठित नियम 8 के खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त भारत सरकार गृह मन्त्रालय नई दिल्ली, जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 और धारा 17-क के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनगणना की तारीख तथा अवधि जिसके दौरान मकानसूचीकरण और जनगणना, 2011, जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन होगी, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 9/7/2009 सीडी (सेन) (का0आ0 517 (अ)) तारीख 25 फरवरी, 2010 तथा भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II खण्ड-3-उप-खण्ड (ii) तारीख 2 मार्च, 2010 को प्रकाशित, को हिमाचल प्रदेश की जनसाधारण की सामान्य सूचना हेतु पुनः प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा,
आशा स्वरूप,
मुख्य सचिव।

[Authoritative English text of this department Notification No. GAD-B(B)15-1/2010 Dated 01-04-2010 as required under clause(3) of article 348 of the constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION*Shimla-171002, the 1st April, 2010*

File No. GAD-B(B)15-1/2010.—In exercise of the powers conferred by clause (iii) of rule 8 of the Census rules, 1990, read with Rule 6 of the Census Rules, 1990 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to re-publish the Notification No.9/7/2009 –CD(CEN) dated 25th February, 2010 [S.O.517(E)] published in the Extraordinary Gazette of India Part II. Section 3 of Sub- Section (ii) regarding the date for the census and the period during which house listing operations and population Census, 2011 will take place under Section 3 of the Census Act, 1948 issued by the Registrar General and Census Commissioner, India, Ministry of Home Affairs, New Delhi in exercise of powers conferred upon them under section 3 and Section 17-A of the Census Act, 1948 for the general information of the public of Himachal Pradesh.

By order,
ASHA SWARUP,
Chief Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग
ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 1 अप्रैल, 2010

संख्या जीएडी-बी(बी)-15-1/2010.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के महारजिस्ट्रार एवं आयुक्त जनगणना, भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, नई दिल्ली, जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के आशय की घोषणा के बारे में समस्त जनगणना अधिकारियों को, उनकी नियुक्ति से सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर भारत की जनगणना, 2011, के सम्बन्ध में मकानसूचीकरण तथा मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए नीचे उल्लिखित मदों के सम्बन्ध में सभी व्यक्तियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछने से सम्बन्धित निर्देश देते हुए, उनके द्वारा जारी अधिसूचना एफ संख्या: 9/7/2009-सीडी(सेन) तारीख 25 फरवरी, 2010 (का0आ0 518(अ)) और भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II खण्ड 3- उप खण्ड (ii) तारीख 2 मार्च, 2010 को, हिमाचल प्रदेश की जनसाधारण की सामान्य सूचना के लिए पुनः प्रकाशित करती है ।

आदेश द्वारा,
आशा स्वरूप,
मुख्य सचिव।

[Authoritative English text of this department Notification No. GAD-B(B)15-1/2010 Dated 01-04-2010 as required under clause(3) of article 348 of the constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
B-Section

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 1st April, 2010

File No. GAD-B(B)15-1/2010.— In exercise of the powers conferred by Clause(i) of Rule 8 of the Census Rules, 1990 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to re-publish the Notification F No. .9/7/2009-CD(CEN) dated 25th February, 2010 [S.O.518(E)] and published in the Gazette of India Extraordinary Part-II-Section 3-Sub Section (ii) on dated 2nd March, 2010 regarding declaration of intention of the Central Government to instruct all the Census Officers within the limits of the local area for which they have been respectively appointed to ask all such questions from the persons on the items enumerated for collecting information through the Houselisting and housing Census schedules in connection with the census of India, 2011, issued by the Registrar General and Census Commissioner, India Ministry of Home Affairs, New Delhi in exercise of powers conferred upon them under section 3 of the Census Act, 1948 for the general information of the public of Himachal Pradesh.

By order,
ASHA SWARUP,
Chief Secretary.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 2, 2010/फाल्गुन 11, 1931

No. 435]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 2, 2010/PHALGUNA 11, 1931

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2010

का.आ. 517(अ).—जनगणना नियमावली, 1990 के नियम 6क के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 एवं धारा 17क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि भारत की जनगणना 2011 से संबंधित मकानसूचीकरण का कार्य 1 अप्रैल, 2010 से 30 सितम्बर, 2010 तक विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में किया जाएगा।

[फा. सं. 9/7/2009-सीडी (सेन)]

च. चन्द्रमौलि, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2010

S.O. 517(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 and Section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948) read with rule 6A of the Census Rules, 1990, the Central Government hereby declares that the Houselisting Operations of Census of India 2011 shall take place from 1st April, 2010 to 30th September, 2010 in different States and Union Territories.

[F. No. 9/7/2009-CD (CEN)]

C. CHANDRAMOULI, Registrar General and Census Commissioner, India

826 GI/2010

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2010

का.आ. 518(अ).—जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 8 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अनुदेश देती है कि सभी जनगणना अधिकारी उनकी नियुक्ति से संबंधित स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर भारत की जनगणना 2011 के संबंध में मकानसूचीकरण तथा मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए नीचे उल्लिखित मदों के संबंध में सभी व्यक्तियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछें, अर्थात् :—

1. भवन नम्बर (नगर अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नम्बर)
2. जनगणना मकान नम्बर
3. जनगणना मकान के फर्श, दीवार तथा छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
4. जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएँ
5. जनगणना मकान की हालत
6. परिवार क्रमांक
7. इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या :
(i) व्यक्ति
(ii) पुरुष
(iii) स्त्री
8. परिवार के मुखिया का नाम
9. लिंग
10. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से संबंधित हों
11. इस मकान के स्वामित्व की स्थिति

(1)

12. इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या
13. परिवार में रहने वाले विवाहित दम्पतियों की संख्या
14. पेयजल का मुख्य स्रोत
15. पेयजल स्रोत की उपलब्धता
16. प्रकाश का मुख्य स्रोत
17. परिसर के भीतर शौचालय
18. शौचालय की सुविधा का प्रकार
19. गन्दे पानी की निकासी
20. स्नानगृह की सुविधा
21. रसोई घर
22. खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन
23. रेडियो/ट्रांजिस्टर
24. टेलीविजन
25. कम्प्यूटर/लैपटॉप
26. टेलीफोन/मोबाइल फोन
27. साइकिल
28. स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड
29. कार/जीप/वैन
30. बैंकिंग सेवा का उपयोग कर रहे हैं।

टिप्पणी : मद सं. 1 से 5 भवन के विवरणों से, मद सं. 6 से 7 परिवार के विवरणों (पूर्णतः अथवा अंशतः आवासीय उपयोग में लाए गए जनगणना मकान के लिए) से, मद सं. 8 से 10 परिवार के मुखिया से और मद सं. 9 से 30 केवल सामान्य परिवार से संबंधित है।

[फा. सं. 9/7/2009-सीडी (सेन)]

च. चन्द्रमौलि, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2010

S.O. 518(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Central Government hereby instructs that all Census Officers may, within the limits of the local areas for which they have been respectively appointed, ask all such questions from all persons on the items enumerated below for collecting information through the Houselisting and Housing Census Schedules in connection with the Census of India 2011, namely :—

1. Building number (Municipal or local authority or census number).
2. Census House number.
3. Predominant material of floor, wall and roof of the census house.
4. Ascertain the use of census house.

5. Condition of the census house.
6. Household Number.
7. Total number of persons normally residing in the household :
(i) Persons
(ii) Males
(iii) Females
8. Name of the head of the household.
9. Sex.
10. If Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Others.
11. Ownership status of the house.
12. Number of dwelling rooms exclusively in possession of the household.
13. Number of married couple(s) living in the household.
14. Main source of drinking water.
15. Availability of drinking water source.
16. Main source of lighting.
17. Latrine within the premises.
18. Type of latrine facility.
19. Waste water outlet.
20. Bathing facility.
21. Kitchen.
22. Fuel used for cooking.
23. Radio/Transistor.
24. Television.
25. Computer/Laptop.
26. Telephone/Mobile phone.
27. Bicycle.
28. Scooter/Motor Cycle/Moped.
29. Car/Jeep/Van.
30. Availing banking services.

Note : Items 1 to 5 relate to Building particulars, items 6 to 7 relate to Household particulars (for census house used wholly or partly as a residence), items 8 to 10 relate to Head of the Household, and items 9 to 30 relate only to Normal Households.

[F. No. 9/7/2009-CD(CEN)]

C. CHANDRAMOULI, Registrar General and Census Commissioner, India

